उत्कृष्टता के नए स्तर सृजित करते हुए

4 वर्षों की उपलब्धियां

भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय

"अब तक, हम सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को नवरत्न कम्पनियां मानते रहे हैं। लेकिन अब, समय इससे परें सोचने का है। क्या हम नए भारत को अनमोल रत्न बनाने के बारे में सोच सकते हैं..."

श्री नरेन्द्र मोदी
भारत के माननीय प्रधानमंत्री

श्री अनन्त ग. गीते
माननीय भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री

श्री बाबुल सुप्रियो
माननीय भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री

विजन

आधुनिक,

स्वस्थ एवं सुदृढ़ ऑटो,

हेवी इंजीनियरिंग, हेवी इलेक्ट्रिकल एवं

केपिटल गुड्स सेक्टर्स

और

विभाग के अधीन आत्म–निर्भर एवं विकासोन्मुख

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम।

मिशन

भारी उद्योग विभाग अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन लाभ अजित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने के साथ–साथ रुग्ण और हानि में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का पुनर्गठन और पुनरुद्धार करने का प्रयास करता है।

भारी उद्योग विभाग राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना परियोजना (नेट्रिप) के माध्यम से अत्याधुनिक अनुसंधान और परीक्षण अवसंरचना का सृजन करके वैश्विक ऑटोमोटिव उत्कृष्टता के अपनेविजन को प्राप्त करने की कोशिश करता है।

भारी उद्योग विभाग ऑटो, हेवी इंजीनियरिंग, हेवी इलेक्ट्रिकल और कैपिटल गुड्स सेक्टर को आवश्यक सहायता प्रदान करके अपने विजन को प्राप्त करने की कोशिश करता है।

फेम – इंडिया

फेम–इंडिया स्कीम ख्भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण, परिवहन में हाइब्रिड/इलेक्ट्रिक प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई थी, जिससे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम हो सके।

इस संपूर्ण स्कीम को 6 वर्ष की अवधि में, वर्ष 2020 तक, लागू करना प्रस्तावित है।

इसमें हाइब्रिड/इलेक्ट्रिक वाहनों के बाजार के विकास और इसके विनिर्माण के पारिस्थितिकी–तंत्र कोप्रोत्साहन देने का इरादा है ताकि निर्धारित अवधि की समाप्ति तक आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सके।

ऑटोमोटिव उद्योग

फेम इंडिया स्कीम–पिछले चार वर्षों के दौरान उपलब्धियां

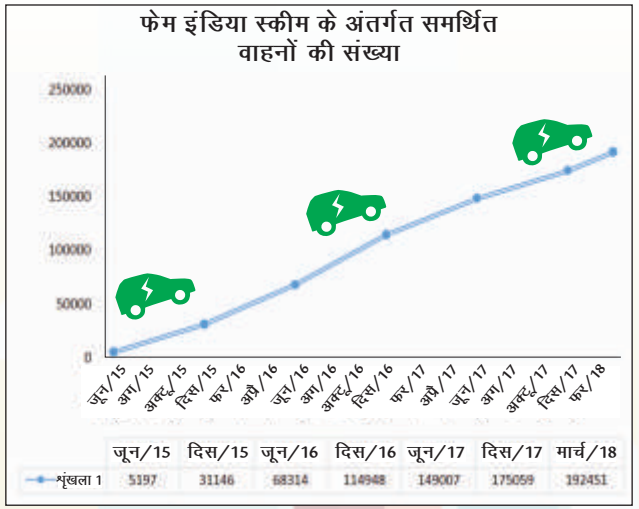

	जून/15	दिस/15	जून/16	दिस/16	जून/17	दिस/17	मार्च/18
शृंखला 1	5197	31146	68314	114948	149007	175059	192451

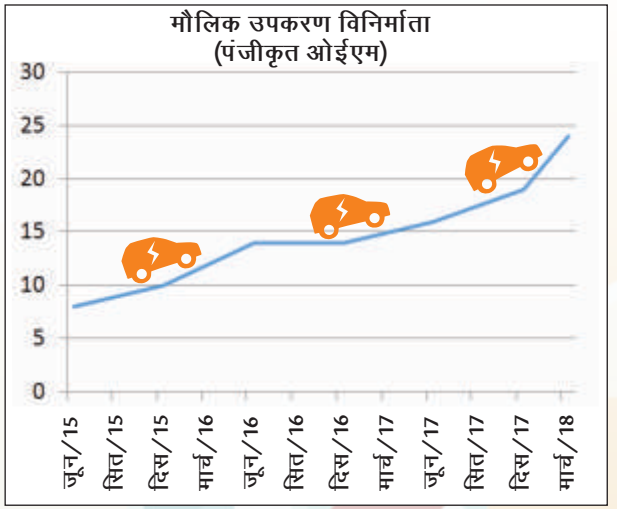

फेम इंडिया स्कीम के अंतर्गत समर्थित वाहनों की संख्या

क्र.सं	वाहन का प्रकार	2015-16	2016-17	2017-18	कुल
1.	दुपहिया	17,850	21,229	47,912	86,991
2.	तिपहिया	शुन्य	शुन्य	2,202	2,202
3.	चौपहिया	30,995	66,476	185	97,656
4.	हल्के वाणिज्यिक वाहन	शुन्य	11	10	21
5.				**कुल समर्थित वाहन**	**1,86,870**

माननीय मंत्री (भारी उद्योग एवं लोक उद्यम) ने माननीय राज्य मंत्री (भारी उद्योग एवं लोक उद्यम) और सचिव, भारी उद्योग की उपस्थिति में इलेक्ट्रिक वाहनों पर सम्मेलन को संबोधित किया।

एमएमआरडीए, मुम्बई के लिए माननीय मंत्री (भारी उद्योग एवं लोक उद्यम) द्वारा फेम इंडिया स्कीम के अंतर्गत हाईब्रिड वाहनों का शुभारंभ ।

27226096 ईंधन की बचत (लीटर में)	प्रति दिन 46423 ईंधन की बचत (लीटर में)	प्रति दिन 115596 सीओ$_2$ की कमी (किग्रा. में)	68162544 सीओ$_2$ की कमी (किग्रा. में)

दिनांक 23 मई, 2018, सायं 7.00 बजे लिए गए आंकड़े, नवीनतम आंकड़े फेम इंडिया पोर्टल में उपलब्ध हैं।

सार्वजनिक एवं साझा परिवहन में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी

सार्वजनिक परिवहन में ई–मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए विभाग ने 31 अक्तूबर, 2017 को इलेक्ट्रिक पावरट्रेन पर आधारित सार्वजनिक और साझा मोबिलिटी आरम्भ करने की घोषणा की थी।

यह रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) की पद्धति के माध्यम से किया गया, जिसमें दस लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों एवं विशेष श्रेणी के राज्यों में इलेक्ट्रिक बसों, इलेक्ट्रिक–चौपहिया वाहनों, यात्री कारों और इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों पर मांग प्रोत्साहन का प्रस्ताव दिया गया।

इस ईओआई में 21 राज्यों के 44 शहरों से 47 प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिसमें 3144 ई–बसों, 2430 ई–चौपहिया वाहनों, टैक्सियों और 21545 ई–तिपहिया ऑटो की मांग की गयी है।

इसके अंतर्गत फेम इंडिया स्कीम के तहत आंशिक रूप से वित्तपोषित 480 बसें, 720 तिपहिया ऑटों और 370 चौपहिया टैक्सियां 11 विभिन्न शहरों को आबंटित की गई।

नेट्रिप

भारत में विश्वस्तरीय ऑटोमोटिव परीक्षण एवं आधिकारिक प्रमाणन की सुविधा को स्थापित करने की परिकल्पना राष्ट्रीय मोटरवाहन परीक्षण तथा अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना परियोजना (नेट्रिप) में की गई है।

हाल ही में, वर्तमान सरकार के प्रयासों से नेट्रिप परियोजना प्रगति पर है।

सीसीईए ने जून, 2019 तक की संशोधित समय–सीमा के साथ ₹ 3727.30 करोड़ की कुल लागत के साथ दूसरे संशोधित लागत अनुमान (आरसीई–II) को अनुमोदित किया है।

आज की तारीख तक पूरे हुए कार्य की कुल लागत ₹ 2691.98 करोड़ है।

राष्ट्रीय ऑटोमिटिव परीक्षण एवं अनुसंधान और विकास अवसंरचना परियोजना (नेट्रिप)

गत चार वर्षों में पूर्ण की गई मुख्य सुविधाएं

आईसीएटी : अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी केंद्र
एनआईएआईएमटी : राष्ट्रीय अनुरक्षण, रखरखाव एवं प्रशिक्षण संस्थान
नैट्रेक्स : राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण ट्रैक्स
एआरएआई : भारतीय ऑटोमोटिव अनुसंधान संघ
जीएआरसी : वैश्विक ऑटोमोटिव अनुसंधान केंद्र

इसके अतिरिक्त, एआरएआई और आईसीएटी, जीएआरसी को भी एक मान्यता प्राप्त संस्थान के रूप में अनुमोदित किया गया है और भारत में केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के तहत होमोलोगेशन परीक्षण एजेन्सियों के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है।

*नक्शा पैमाने पर नहीं है

केपिटल गुड्स उद्योग

राष्ट्रीय केपिटल गुड्स नीति

केपिटल गुड्स सेक्टर के विकास में भारी उद्योग विभाग की भूमिका

राष्ट्रीय केपिटल गुड्स नीति वर्ष 2016 में शुरू की गई थी। राष्ट्रीय केपिटल गुड्स नीति के आरम्भ होने के बाद से ही भारी उद्योग विभाग पॉलिसी में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उद्योग के साथ गहनता से कार्य कर रहा है जो केपिटल गुड्स सेक्टर में अन्य चीजों के साथ उत्पाद एवं रोजगार के अवसरों को तीन गुना अधिक करने के लिए है। पॉलिसी में क्षेत्र की जरूरतों को तुरंत पूरा करने तथा क्षेत्र की वृद्धि तथा विकास को अग्रसक्रिय रूप से सुविधाजनक बनाने की परिकल्पना की गई है।

केपिटल गुड्स सेक्टर की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि हेतु स्कीमः

यह योजना अवसंरचना की लागतों को कम करने के दौरान तकनीक को बढ़ावा देने के लिए नवंबर, 2014 में शुरू की गई थी।

मुख्य पहल/ स्कीम का नाम	केपिटल गुड्स सेक्टर की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि हेतु स्कीम
उद्देश्य	केपिटल गुड्स सेक्टर की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि हेतु स्कीम का उद्देश्य साझा औद्योगिक सुविधा केन्द्रों की स्थापना करने के अतिरिक्त प्रौद्योगिकी गहनता के सृजन के मुद्दों का समाधान करके केपिटल गुड्स सेक्टर को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाना है।
लक्षित लाभार्थी	भारतीय केपिटल गुड्स उद्योग
वास्तविक लक्ष्य	प्रौद्योगिकी विकास हेतु उत्कृष्टता केन्द्र (सीओई), एकीकृत औद्योगिक अवसंरचना सुविधा (आईआईआईएफ), साझा इंजीनियरी सुविधा केन्द्र (सीईएफसी) और परीक्षण एवं प्रमाणन केन्द्र (टीएंडसीसी) स्थापित करना। इस स्कीम में केपिटल गुड्स सेक्टर में प्रौद्योगिकी अधिग्रहण/अंतरण हेतु प्रौद्योगिकी अधिग्रहण निधि कार्यक्रम (टीएएफपी) नामक एक वित्तीय संघटक भी है।
लाभार्थियों की संख्या	संपूर्ण रूप से भारतीय केपिटल गुड्स उद्योग, विशेष रूप से प्रमुख केपिटल गुड्स सब–सेक्टर, जैसे मशीन टूल उद्योग, वस्त्र मशीनरी उद्योग, मोल्ड और डाई उद्योग तथा विद्युत उपकरण भावी लाभार्थी हैं।

भारतीय केपिटल गुड्स सेक्टर की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि हेतु स्कीमः

पिछले चार वर्षों (2014–18) में मुख्य उपलब्धियां (परियोजना अनुमोदन)

निम्नलिखित उत्कृष्टता केन्द्रों का निर्माण निम्न स्थानों पर किया जा रहा हैः

- हाई स्पीड शटललैस रेपियर्स के विकास केलिए केन्द्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान (सीएमटीआई), बेंगलुरू।
- मशीन टूल्स एंड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के लिए 11 अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए आईआईटी, मद्रास।
- इन प्रौद्योगिकियों को स्वदेशी रूप से विकसित करने में एमएसएमई की सहायता के लिए तीन वेल्डिंग प्रौद्योगिकियों के विकास हेतु पीएसजी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, कोयम्बटूर।
- साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रीयल टेस्टिंग एंड रिसर्च सेंटर (एसआईटीएआरसी), कोयम्बटूर, इंडस्ट्रीयल और वाटर सप्लाई एप्लीकेशन्स के लिए स्मार्ट सबमर्सिबल पंपिंग सोल्यूशंस।
- वस्त्र मशीनरी हेतु आईआईटी, दिल्ली। उत्पाद विकास पर फोकस केसाथ–मुख्यतः आयात विकल्प और उन्नत उत्पाद प्रौद्योगिकियां।
- उद्योग संबंधी प्रौद्योगिकियों के विकास हेतु उन्नत विनिर्माण के लिए आईआईटी, खड़गपुर।

उत्कृष्टता केंद्र

साझा इंजीनियरी सुविधा (सीईएफसी)

निम्नलिखित साझा इंजीनियरिंग सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा हैः

- टेग्मा द्वारा टूल्स, मोल्ड्स एवं डाइज उद्योग के लिए पुणे के पास चाकन।
- रांची में सीईएफसी प्रथम फाउन्डेशनः केपिटल गुड्स सेक्टर में कौशल अंतर को दूर करने के लिए कुशल जनशक्ति को प्रशिक्षित एवं विकसित करना।
- बारदोली, सूरत में साइंस इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजिकल अपलिफ्टमेंट (एसईटीयू) फाउंडेशन। टेक्सटाइल इंजीनियरी उद्योग की जरूरतों को पूरा करने केलिए इसमें डिजाइन सेंटर, टूल रूम, प्रशिक्षण केन्द्र और परीक्षण लैब की आवश्यकता।
- 3डी प्रिंटिंग टेक्नालॉजीज, सिस्टम्स एवं मेटेरियल्स के डिजाइन एवं विकास हेतु विपरो 3डी सहित आईआईएससी बेंगलोर।
- स्टील इक्विपमेंट डिजाइन इंजीनियर्स के कौशल विकास हेतु बहादुरगढ़ में मै. कोरस इंजीनियरिंग साल्यूशंस प्रा. लि.।

टीएएफपी एंड इंडस्ट्रीयल पार्क

टीएएफपी के तहत पीटीसी इंडस्ट्रीज लि. द्वारा सिरेमिक शेलिंग प्रौद्योगिकी सहित टाइटेनियम कास्टिंग के विकास एवं वाणिज्यिकी करण हेतु प्रौद्योगिकी अधिग्रहण। यह प्रौद्योगिकी भारत में पहली बार लाई जा रही है।

कर्नाटक सरकार द्वारा तुमकुर, कर्नाटक के समीप एकीकृत मशीन टूल्स पार्क पर एकीकृत औद्योगिक अवसंरचनात्मक सुविधा (आईआईआईएफ)। इस पार्क की स्थापना का उद्देश्य देश में मशीन टूल्स के उत्पादन को दोगुना करना है।

समर्थ उद्योग – उद्योग 4.0 केन्द्र

उद्योग 4.0 काकार्यान्वयन आरंभ करने में एसएमई को सुकर बनाने के लिए भारी उद्योग विभाग अपनी केपिटल गुड्स स्कीम के अन्तर्गत उद्योग 4.0 के नवाचार, प्रदर्शन और अनुभव केन्द्रों को स्थापित करने में सहयोग दे रहा है।

यह कल्पना की गई है कि ये राष्ट्रीय केन्द्र, ''एसएएमएआरटीएच (स्मार्ट एंड एडवांस्ड मैन्युफैक्चिरंग एंड रैपिड ट्रासेफोरमेशन हब) उद्योग'' उद्योग 4.0 के अंगीकरण हेतु पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में मदद करेंगे।

समर्थ उद्योग, विनिर्माण उद्योग, विशेष रूप से सूक्ष्म एवं मध्यम क्षेत्र, को इन प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए प्रायोगिक परीक्षण और हैंड होल्डिंग सपोर्ट के लिए एक परिचालन मंच प्रदान करेगा।

विभाग, हमारे उद्योग के मध्य उद्योग 4.0 को अपनाने के लिए चलाए जा रहे जागरूकता अभियान को बढ़ावा दे रहा है।

भारी उद्योग विभाग दिल्ली, पुणे और बेंगलुरू में चार उद्योग 4.0 केन्द्रों/समर्थ उद्योग को भी बढ़ावा दे रहा है।

ये 'डेमो सह अनुभव' केन्द्र देश के विभिन्न हिस्सों में स्मार्ट और अत्याधुनिक विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किए जा रहे हैं।

डेमो सह अनुभव केन्द्र

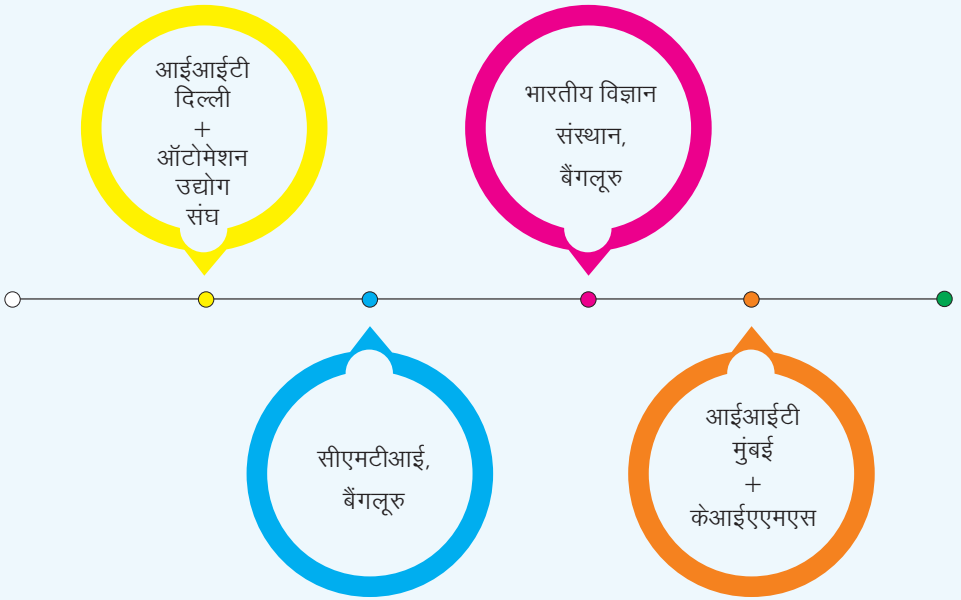

सीएमटीआई : केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान

केआईएएमएस: किर्लोस्कर उन्नत प्रबंधन अध्ययन संस्थान

हेवी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उद्योग

ताप विद्युत संयंत्रों के लिए उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल (एयूएससी) प्रौद्योगिकी का विकास

आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने दिनांक 10 अगस्त, 2016 को ताप विद्युत संयंत्र के लिए उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल (एयूएससी) विकास प्रौद्योगिकी के विकास हेतु अनुसंधान एवं विकास परियोजना के भारी उद्योग विभाग के प्रस्ताव को अनुमोदित किया।

यह अनुसंधान एवं विकास परियोजना कोयले की खपत और कार्बन डाइ–ऑक्साइड के उत्सर्जन दोनों में 11% की कमी के साथ भविष्यवादी स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी में आईपी अधिकारों के साथ भारत को वास्तविक डेवलेपर और धारक बनायेगा। यह देश के लिए एक विशाल कोयला भंडार के साथ दीर्घावधिक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, जो आज से ज्यादा अच्छी और अधिक कुशल तरीके से उपयोगकी जासकती है।

कोयले की खपत में कमी के साथ–साथ कार्बन उत्सर्जन में कमी को परिकल्पित करते हुए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्यम, के नेतृत्व में डीएसटी, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान संस्थान (आईजीसीएआर) और नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन (एनटीपीसी) के साथ तीन सरकारी इकाइयों के कंसोर्टियम ने भविष्य के ताप विद्युत केन्द्रों के लिए एयूएससी प्रौद्योगिकी के विकास हेतु अनुसंधान एवं विकास परियोजना का प्रस्ताव किया है।

यह परियोजना ढाई वर्ष के लिए बनाई गई है, जिसकी लगभग लागत ₹ 1554 करोड़ है, जिसमें बीएचईएल से ₹ 270 करोड़, एनटीपीसी से ₹ 50 करोड़, आईजीसीएआर से ₹ 234 करोड़, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) से ₹ 100 करोड़ का योगदान है। ₹ 900 करोड़ की शेष राशि भारी उद्योग विभाग द्वारा अनुदान के रूप में दी जाएगी।

परियोजना के अनुसंधान एवं विकास चरण के बाद एक प्रदर्शन परियोजना होगी जिसमें नेशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन (एनटीपीसी) द्वारा इस प्रौद्योगिकी के साथ एक 800 मेगावाट थर्मल पॉवर प्लांट स्थापित किया जाएगा।

भारी उद्योग विभाग ने इस परियोजना के लिए वर्ष 2017–18 में ₹ 120 करोड़ जारी किए हैं। यह परियोजना भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के निर्देशन में समय से प्रगति पर है।

माननीय मंत्री (भारी उद्योग एवं लोक उद्यम) ने माननीय राज्य मंत्री की उपस्थिति में जीएआरसी, चैन्नई में परिक्षण ट्रैक सुविधाओं का उदघाटन किया।

माननीय मंत्री (भारी उद्योग एवं लोक उद्यम) ने अंतरराष्ट्रीय ऑटोमोटिव प्रद्योगिकी केन्द्र (आईसीएटी), मानेसर की अनेक परिक्षण सुविधाओं का उदघाटन किया।

एआरएआई, पुणे में आयोजित तीन दिवसीय, सम्मेलन, आईटीईसी इंडिया 2017 में माननीय मंत्री (भारी उद्योग एवं लोक उद्यम)। उन्होंने एआरएई दवारा विकसित इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के 'उत्कृष्ता केन्द्र' का भी शुभारंभ किया।

माननीय मंत्री (भारी उद्योग एवं लोक उद्यम) ऑटो एक्सपो 2018 का उदघाटन करते हुए।

माननीय मंत्री (भारी उद्योग एवं लोक उद्यम) द्वारा बरदौली, सुरत, गुजरात में एक सीईएफसी, एसईटीयू फाउंडेशन का शिलांयास किया गया।

माननीय राज्य मंत्री (भारी उद्योग एवं लोक उद्यम) द्वारा नेट्रैक्स का उदघाटन

माननीय मंत्री (भारी उद्योग एवं लोक उद्यम) द्वारा चाकन, पुणे में सीईएफसी में टीएजीएमए उत्कृष्टा एवं प्रशिक्षण केन्द्र में ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह

माननीय मंत्री (भारी उद्योग एवं लोक उद्यम) ने बैंगलुरू में भेल की सौर पीवी विनिर्माण लाइनों का उदघाटन किया।

भारी उद्योग विभाग के अंतर्गत केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

भारी उद्योग विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 31 उद्यम हैं।

जिनमें से 10 सीपीएसई लाभ कमा रहे हैं, 12 घाटे में चल रहे हैं, 8 सीपीएसई एवं 2 सीपीएसई के प्रभाग बन्द होने की प्रक्रिया में है।

भारी उद्योग विभाग के पास इंजीनियरींग, परामर्श/संविदा, अन्य विनिर्माण सेक्टर एवं ऑटोमोटिव्स के क्षेत्र में 5 स्वायत्त संगठन हैं।

भारी उद्योग विभाग लाभ कमाने वाले सीपीएसई को कारोबार बढ़ाने/लाभप्रदता और वैश्विक महत्व प्राप्त करने के लिए मजबूती/सहायता प्रदान करता है जबकि हानि उठा रहे सीपीएसई के पुनरुद्धार/पुनर्गठन की सिफारिश करता है।

भारी उद्योग विभाग के नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की पिछले चार वर्षों की उपलब्धियां

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल)

इस कंपनी के पास 17 विनिर्माण इकाइयों, 2 मरम्मत इकाइयों, 4 क्षेत्रीय कार्यालयों, 8 सर्विस सेंटरों, 1 सहायक कम्पनी, 3 विदेश स्थित कार्यालयों, 6 संयुक्त उद्यमों, 15 क्षेत्रीय विपणन केन्द्रों का विशाल नेटवर्क है। सम्पूर्ण भारत और विदेश में 150 से अधिक परियोजना स्थलों पर चालू परियोजनाओं का निष्पादन इसके विशाल पैमाने और आकार की पुष्टि करता है।

बीएचईएल विश्व की उन कुछेक कंपनियों में से एक है जिसमें बिजली संयंत्र उपकरण की संपूर्ण श्रृंखला के विनिर्माण की क्षमता है और संकल्पना से लेकर कमीशनिंग तक बिजली परियोजनाओं के निष्पादन की प्रमाणित टर्नकी क्षमताएं हैं।

बीएचईएल रक्षा के क्षेत्र में 'मेक इन इंडिया' की पहल के साथ फील्ड गन, पनडुब्बी आदि के क्षेत्र में सक्रिय रूप से बड़े सुअवसरों की तलाश में है।

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसारबीएचईएल का भारत की कुल संस्थापित क्षमता में 50% हिस्सा और देश के कुल उत्पादन में 58% हिस्सा थर्मल यूटिलिटी सेट (कोयला आधारित) है, जो राष्ट्र निर्माण में इसके मूल्यवान योगदान की गवाही देता है।

बीएचईएल ने कावासाकी हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (केएचआई), जापान के साथ मेट्रो केलिए स्टेनलेस स्टील के कोच और बोगियों के विनिर्माण के लिए टेक्नालॉजी कोलेबोरेशन एग्रीमेन्ट (टीसीए) किया है। केएचआई के साथ प्रौद्योगिकी समझौता से शहरी परिवहन व्यवसाय में 'मेक इन इंडिया' की पहल और बीएचईएल के विविधीकरण को भी बढ़ावा मिला है।

बीएचईएल ने 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) के दौरान 45,274 मेगावाट क्षमता संयोजन हासिल किया जो भारत सरकार द्वारा उनके लिए निर्धारित 41,661 मेगावाट के लक्ष्य से 9% अधिक है।

800–मेगावाट कोल्डम हाइड्रो पावर प्लांट

250– मेगावाट बोंगईगांव थर्मल पावर स्टेशन

सुरक्षा सरोकारों और विशाल लॉजिस्टक बाधाओं के बावजूद, बीएचईएल ने अफगानिस्तान में प्रतिष्ठित 3×14 मेगावाट सलमा जल विद्युत परियोजना (अफगान भारत मैत्री बांध) की सभी तीनों इकाइयों को सफलतापूर्वक चालू कर दिया है।

बीएचईएल ने 2×800 मेगावाट के वाणिज्यिक ऑपरेशन शुरू करके केपीसीएल, बीएचईएल और आईएफसीआई के संयुक्त उद्यम, आरपीसीएल के येरामारस टीपीएस में बिजली उत्पादन की शुरुआत की है।

बांग्लादेश में 1,320 मेगावाट की मैत्री सुपर थर्मल पॉवर परियोजना को स्थापित करने केलिए बीएचईएल की ₹ 10,000 करोड़ (1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर) की सबसे बड़ी विदेशी परियोजना शुरु हो गई है और कार्य अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है।

कंपनी का अनुसंधान एवं विकासव्यय अब 5 से अधिक वर्षों के कारोबार का 2.5% से अधिक रहा है। फोर्बिस ने विश्व की 100 सर्वाधिक अभिनव कंपनिया, 2011 की सूची में बीएचईएल को 9वां स्थान दिया है। मार्च, 2018 के अनुसार कम्पनी की पेटेंट/कॉपी राइट की बौद्धिक पूंजी 4,300 से अधिक थी।

बीएचईएल थर्मल पॉवर प्लांट्स के लिए उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल (एयूएससी) के विकास हेतु एक महत्वाकांक्षी अनुसंधान एवं विकास परियोजना का नेतृत्व कर रहा है, जो स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देगी और कार्बन उत्सर्जन को 11% तक कम करेगी।

एंड्रूय यूल एंड कंपनी लिमिटेड (एवाईसीएल):

पिछले कुछ वर्षों से, एवाईसीएल के चाय डिविजन उद्योग को ''शीर्ष गुणवत्ता चाय निर्माता'' में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है।

नार्थ इंडियन बैटिंग ऑडर के अनुसार; वित्तीय वर्ष 2016–17 में शीर्ष 10 में 4 (चार) शीर्ष 11 और शीर्ष 20 के बीच 4 (चार) उद्यान दिखाए गए हैं और उद्यान/विनिर्माण इकाइयों को शेष शीर्ष 21 और 29 के बीच दिखाया गया है।

वित्त वर्ष 2016–17 में चाय का उत्पादन 102.34 लाख किलो तक बढ़ गया है। आज एवाईसीएल विश्व के कई देशों में चाय का निर्यात कर रहा है।

वित्त वर्ष 2016–17 में ₹ 90.00 करोड़ का उच्चतम कारोबार इलेक्ट्रिक डिवीजन–कोलकाता ऑपरेशन में हासिल किया गया है और इसी वित्तीय वर्ष में इलेक्ट्रिकल डिवीजन–चेन्नई ऑपरेशन ने भी ₹ 66.90 करोड़ का उच्चतम कारोबार किया है।

''कार्पोरेट सामाजिक गतिविधियां'' (सीएसआर) के अंतर्गत अपनी पहल के रूप में कंपनी ने शिक्षा, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, जल स्वच्छता, ग्राम विकास आदि के क्षेत्र में अपनी परियोजनाएं पूरी की।

एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड, चेन्नई

स्वायत्त निकाय

ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई) की स्थापना वर्ष 1966 में की गई और एआरएआई– फोर्जिंग इंडस्ट्री डिवीजन (एआरएआई–एफआईडी) पुणे, महाराष्ट्र की स्थापना वर्ष 2006 में हुई थी।

अंशांकन के लिए प्रवाह उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए जुलाई, 1987 में फ्लूइड कंट्रोल रिसर्च इंडस्टीट्यूट (एफसीआर), पलक्कड़, केरल की स्थापना की गई थी।

राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना परियोजना (नेट्रिप) के कार्यान्वयन को गति देने के लिए जुलाई, 2005 में नेट्रिप कार्यान्वयन सोसाइटी (नेटिस) की स्थापना की गई थी।

ऑटोमोटिव सेक्टर में सरकार के सभी प्रयासों को संचार रूप से आगे बढ़ाने, समन्वय स्थापित करने और तालमेल कायम करने के लिए वर्ष 2012 में नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड (एनएबी) की स्थापना की गई थी।

विभिन्न सीएसआर गतिविधियों पर कंपनी ने वर्ष 2013-14 को दौरान ₹ 37.10 लाख, वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 27.17 लाख, 2015-16 के दौरान ₹ 32.69 लाख और वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 27.95 लाख का व्यय किया।

राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड (आरईआईएल), जयपुर

आरईआईएल 100 से अधिक प्रकार के उत्पादों को बनाकर देश में सबसे बड़े दुग्ध विश्लेषक नियोक्ता और महत्वपूर्ण ऑफ ग्रिड/ऑन ग्रिड सौर समाधान प्रदाता के रूप में उभरा है। इन नवाचारों ने 6 करोड़ नागरिकों और 3 लाख गांवों को लाभान्वित किया है और अब प्रतिवर्ष 10,000 गांवों को कवर करने का लक्ष्य है।

ग्रामीण पेय जल मिशन को आगे बढ़ाने के लिए पूरे राजस्थान राज्य में लगभग 784 साइटों पर गावों/आवासों में कम मांग वाले क्षेत्रों में बोर–वेल आधारित योजनाओं में रिमोट मॉनिटरिंग यूनिट (आरएमयू) समाधान के साथ सौर प्रकाश वोल्टीय (एसपीवी) जल पम्प उपलब्ध कराए है।

वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने के माननीय प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप, भारत की पहली प्रायोगिक परियोजना नेशनल डेयरी डवलपमेंट बोर्ड और इन्टरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के सहयोग से मुजकुवा सौर ऊर्जा उत्पादक सहकारी मंडली के लिए एकीकृत सौर जल पंप किसान कॉ–ऑपरेटिव को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है।

आरईआईएल ने फेम इंडिया स्कीम के तहत प्रोटोटाइप एसपीवी आधारित हाइब्रिड चार्जिंग स्टेशन विकसित किए और अब इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जयपुर, चंडीगढ़ और दिल्ली में नेशनल मिशन फॉर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (एनएमईएम) के अंतर्गत चार्जर लगाने के लिए परियोजनाओं पर कार्य कर रही है।

रेलवे स्टेशनों पर विश्वस्तरीय आधारभूत संरचना स्थापित करने केलिए माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पर 1 मेगावाट सोलर पावर प्लांट परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा करने लिया गया है और अब संबंधित पीएसयू, रेलवे, रक्षा और कई मंत्रालयों के लिए मेगावाट आकार परियोजनाओं पर काम कर रही है।

राजस्थान के स्मार्ट शहरों–अजमेर, जयपुर, कोटा और उदयपुर में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेन्सी और परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी) के रूप में कार्य कर रही है।

डीपीयू विनिर्माण राजस्थान इलेक्ट्रानिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (रील), जयपुर

ग्रामीण आवास के लिए होम लाईटिंग सोल्यूशन

ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (बीबीजे) :

बीबीजे और बीबीयूएनएल का हाल ही में एक एकीकृत इकाई के रूप में विलय हो गया है। बीबीजे ने वर्ष 2014–15, 2015–16, 2016–17 और 2017–18 के दौरान क्रमशः ₹ 74.06 करोड़, ₹ 68.89 करोड़, ₹ 28.04 करोड़ और ₹ 4.86 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया है। यह कंपनी 2009–10 से ही लाभांश का भुगतान करने वाली कंपनी है। भारत सरकार को 2015–16 और 2016–17 के दौरान क्रमशः ₹ 13.32 करोड़ और ₹ 6.36 करोड़ के लाभांश का भुगतान किया गया था।

बीबीजे ने बिहार के मुंगेर में गंगा नदी के ऊपर 4 किमी लंबी रेल सह सड़क पुल की आपूर्ति, फैब्रिकेशन और इरेक्शन का कार्य पूरा कर लिया है। पुल का उद्घाटन 12.03.2016 को भारत के माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा किया गया था।

बीबीजे ने निम्नलिखित प्रमुख आदेश हाल ही में प्राप्त किए हैं: –

- ओडिसा, छत्तीसगढ़ और यूपी में तीन केन्द्रीय विद्यालयों के निर्माण के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली से आदेश प्राप्त हुआ।
- पूर्वोत्तर सड़क क्षेत्र विकास योजना के अधीन सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में सड़क और पुलों के निर्माण के लिए पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) और बीबीजे के बीच समझौता पर हस्ताक्षर किए गए।
- एशिया के सबसे ऊँचे पियर, मणिपुर मेंखोंगसांग स्टेशन से नोनी स्टेशन केबीच इरांग नदी पर रेलवे पुल नं. 130 और नं. 164 का फैब्रिकेशन और इरेक्शन का कार्य।
- पिछले चार वर्षों से स्वच्छ भारत कोष, गंगा स्फाई निधि, बेरोजगार युवाओं के लिए कौशल विकास तथा स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में पूर्ण सीएसआर निधि खर्च की गई है।

पूर्ण होने के बाद मुंगेर का गंगा पुल

रुग्ण और घाटे में चल रहे सीपीएसईज को समयबद्ध रूप से बन्द करना

भारी उद्योग विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण वाली कुछ सीपीएसई बहुत लंबे समय से रुग्ण हैं और विगत 10–15 वर्षों से निरन्तर घाटे मे चल रही हैं। वे भारत सरकार की बजटीय सहायता पर निर्भर हो गई हैं।

अतः सरकार ने हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, तुंगभद्रा स्टील प्लांट लिमिटेड, एचएमटी वाचिज लिमिटेड, एचएमटी चिनार वाचिज लिमिटेड, एचएमटी बेयरिंग्स लिमिटेड, इंस्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड (कोटा यूनिट) और एचएमटी, ट्रैक्टर डिवीजन, पिंजौर के कर्मचारियों को आकर्षक वीआरएस/वीएसएस की ऑफर देकर बंद कर दिया है।

चल और अचल आस्तियों के निपटान और बकाया देनदारियों को चुकाने की प्रक्रिया चल रही है। लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार भूमि और अन्य चल आस्तियों के निपटान के लिए एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड को भू–प्रबंधन एजेन्सी के रूप में नियुक्त किया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संबंधी कार्यकलापों की एक झलक

माननीय भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री ने 15 सितंबर,2017 को फ्रैंकफर्ट, जर्मनी में आईएए इंडिया डे– इंडिया यूरोप नामक मोटरवाहन प्रौद्योगिकी बैठक में भारी उद्योग विभाग के प्रतिनिधि–मंडल का नेतृत्व किया। आईएए एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है तथा यह ऑटोमोटिव उद्योग की सर्वाधिक व्यापक प्रदर्शनी है। माननीय मंत्री जी ने स्वागत भाषण दिया और उन्हें आईएए के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए भी आमंत्रित किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजन में एक भागीदार के रूप में एक्मा और सियाम जैसी भारतीय ऑटो और ऑटो घटत एसोसिएशनें प्रदर्शनी क्षेत्र ''न्यू मोबलिटी वाहन'' का हिस्सा थी, जिन्होंने कनेक्टेड कारों, स्वचालित ड्राइविंग, गतिशीलता सेवाओं, शहरी गतिशीलता और ई–गतिशीलता जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण गतिशीलता मुद्दों का प्रदर्शन किया।

सचिव (भारी उद्योग) के नेतृत्व में भारी उद्योग विभाग के प्रतिनिधिमंडल ने ''मेक इन इंडिया स्वीडन 2017'' में भाग लेने के लिए 12 से 13 अक्टूबर, 217 तक स्टॉकहोम, स्वीडन का दौरा किया। सचिव (भारी उद्योग) ने ऑटोमोबाइल्स, ऑटो कम्पोनेन्टस और केपिटल गुड्स संबंधी निवेशको गोलमेज (इन्वेस्टर राउंडटेबल्स) कार्यक्रम में स्पीकर के रूप में भाग लिया। इन गोलमेजों (राउंडटेबल्स) ने भारत की ऑटो मोबाइल, ऑटो घटक और केपिटल गुड्स सेक्टरों में स्वयं को निवेश लक्ष्य के रूप में प्रदर्शित करने का उत्कृष्ट अवसर प्रदान किया।

सचिव, भारी उद्योग के नेतृत्व में भारी उद्योग विभाग के एक प्रतिनिधि–मंडल ने 23 से 25 अप्रैल, 2018 तक औद्योगिक प्रदर्शनी हेनोवर मैसे, जर्मनी में भाग लेने तथा समर्थ उद्योग (14.0 प्रदर्शन सह– अनुभव केन्द्र) को कार्यान्वित करने हेतु उद्योग 4.0 के बारे में जर्मन पक्ष से वार्तालाप करने एवं स्मार्ट विनिर्माण हेतु उद्योग 4.0 के संबंध में देश के लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए हेनोवर, जर्मनी का दौरा किया।

चेक गणराज्य के माननीय उद्योग और व्यापार मंत्री श्री एच.ई टॉम हुनर के नेतृत्व में चेक प्रतिनिधि–मंडल ने दिनांक 06.03.2018 को ऑटोमोटिव उद्योग और भारी इंजीनियरी उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों मे द्विपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ करने तथा भारत के साथ व्यापार विनियम एवं पारस्परिक सहयोग बढ़ाने में चेक कंपनियों की भूमिका पर विचार–विमर्श करने के लिए माननीय भारी उद्योग और लोग उद्यम मंत्री के साथ मुलाकात की।

मशीनरी सुरक्षा, ऑटोमोटिक्स में होमोलोगेशन प्रक्रिया एवं इलेक्ट्रो गतिशीलता से संबंधीत विषयों पर भारत–जर्मन सहयोग के संबंध में चर्चा करने के लिए 16 जनवरी, 2018 को डिपार्टमेंट फॉर डिजिटल एंड इनोवेशन पॉलिसी के डायरेक्टर जनरल एवं अध्यक्ष श्री स्टीफन स्कैनर के नेतृत्व में फेडरल मिनिस्ट्री फॉर इक्नोमिक अफेयर्स एंड एनर्जी के प्रतिनिधि–मंडल तथा सचिव (भारी उद्योग) के बीच बैठक हुई।

फुकेट, थाइलैंड में 29–11–2017 से 01–12–2017 के दौरान आयोजित सड़क सुरक्षा संबंधी कार्रवाई–दशक के कार्यान्वयन हेतु कार्रवाई की गति को बढ़ाने के संबंध में डब्लयूएचओ दक्षिण पूर्व एशिया की मंत्रालयी बैठक में भाग लेने के लिए भारी उद्योग विभाग को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के नेतृत्व वाले भारतीय प्रतिनिधि–मंडल में शामिल किया गया था। इस बैठक में संयुक्त सचिव (ऑटो) ने भारी उद्योग विभाग का प्रतिनिधित्व किया।

भारी उद्योग विभाग में स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी)

स्वच्छ भारत मिशन को महात्मा गाँधी के जन्म की 150वीं वर्षगाठ अर्थात 2 अक्टूबर, 2019 तक स्वच्छ भारत के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को हासिल करने के उद्धेश्य से शुरू किया गया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने निदेश दिया है कि प्रत्येक मंत्रालय 2017–18 और 2018–19 के लिए दो वर्ष की स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी) तैयार करे तथा इस 2017–18 के बजट प्रस्तावों में विशिष्ट कार्यकलापों में शामिल करे। तदनुसार, भारी उद्योग विभाग ने 2017–18 और 2018–19 के लिए एसएपी तैयार की तथा स्वच्छ भारत मिशन के नोडल मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता गतिविधियों के लिए भेज दी। स्वच्छता कार्य योजना 2017–18 के तहत इस विभाग ने ₹ 165.25 करोड़ की आवंटित राशि में से ₹ 166 करोड़ खर्च किए।

स्वच्छता ही सेवा

इस विभाग में 15 सितम्बर से 2 अक्टूबर, 2017 तक कीअवधि के दौरान स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया गया तथा इस विभाग के नियंत्रणाधीन सीपीएसई/स्वायत्त निकायों को भी तदनुसार ऐसा ही अभियान चलाने के अनुदेश दिए गए थे।

स्वच्छता पखवाड़ा

माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रैल, 2016 में स्वच्छता पखवाड़ा कि अवधारणा की शुरूआत की थी। इस विभाग और इसके नियंत्रणाधीन प्रचालनरत सभी सीपीएसई/स्वायत्त निकायों ने कलैण्डर वर्ष 2016 में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया।

अनुवर्ती वर्ष 2017 में, 16.12.2017 से 31.12.2017 तक की अवधी के दौरान स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया था। भारी उद्योग विभाग के अधीन सीपीएसई/स्वायत्त निकायों को स्वच्छता पखवाड़ा मानने के महत्व के प्रति जागरुक बनाने के लिए, सचिव (भारी उद्योग) ने संगठनों की तैयारी की समीक्षा करने एवं अपशिष्ट प्रबन्धन और पृथक्करण, अपशिष्ट रिसाइक्लिंग के संवर्धन तथा पुरानें स्टोरों के निपटान हेतु कार्यकलाप शुरु करने के लिए 14.12.2017 को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों/मुख्य कार्यकारी अधिकारियों/प्रबंध निदेशकों के साथ पखवाड़ा पूर्व बातचीत की थी।

स्वच्छता के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए कार्यशालाओं/बैठकों/प्रतिस्पर्धाओं के आयोजन के माध्यम से समुदाय एवं छात्रों की भागीदारी के साथ स्वच्छता संबंधी कार्यकलाप बहुत उत्साहपूर्वक शुरु किए गए थे और इन्हें सोशल मीडिया पर दिखाया गया था। माननीय भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रीं द्वारा दिनांक 27.12.2017 को प्रेस कांफ्रेस में फेम योजना के तहत सार्वजनिक और साझा ई–गतिशीलता के संवर्धन हेतु जारी रुचि की अभिव्यक्ति के तहत चुने गए शहरों की घोषणा भारी उद्योग विभाग के लिए स्वच्छता पखवाड़ा की मुख्य विशेषता थी।

विभाग ने कागजरहित (पेपरलेस) और पर्यावरण के अनुकुल (इको–फ्रेंडली) कार्यालय के साथ–साथ कार्यालय में और अधिक स्वच्छ वातावरण बनाने के उद्देश्य से ई–ऑफिस प्रणाली की शुरुआत कर दी है।

भारी उद्योग विभाग के सीपीएसई और स्वायत्त निकायों के तहत स्वच्छता की विभिन्न गतिविधियां

लोक उद्यम विभाग (डीपीई) का पर्यवेक्षण

लोक उद्यम विभाग (डीपीई) सभी केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों (सीपीएसईज़) का नोडल विभाग है तथा यह सीपीएसईज़ से संबंधित नीतियां तैयार करता है। यह विशेष रूप से कार्मिक एवं मजूरी मामलों, कार्यनिष्पादन सुधार एवं मूल्यांकन, स्वायत्तता एवं वित्तीय प्रत्यायोजन तथा कॉरपोरेट अभिशासन पर दिशानिर्देश निर्धारित करता है। यह लोक उद्यम सर्वेक्षण का प्रकाशन करता है जो सीपीएसईज़ के कार्यनिष्पादन पर एक समेकित रिपोर्ट होती है।

लोक उद्यम विभाग की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां निम्नलिखित हैं :–

न्यूनतम सरकार अधिकतम अभिशासन के उद्देश्य के साथ लगभग दस वर्षों के बाद लोक उद्यम विभाग के पुराने/समाप्त हो चुके दिशानिर्देशों को युक्तिसंगत बनाया गया है। 635 ऐसे दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई और 320 दिशानिर्देशों का एक संकलन जनवरी, 2016 में प्रकाशित किया गया था। संशोधित संकलन को तैयार करने के लिए, दिशानिर्देशों की समीक्षा की प्रक्रिया चालू वर्ष 2017–18 में भी चल रही है।

केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के पुनरुद्धार / पुनर्गठन हेतु निर्णय लेने में बहु–स्तरीय प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए सरकारी लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) को नवम्बर, 2015 में समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद सही समय पर रुग्ण, प्रारंभिक रुग्ण और कमजोर केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों को अभिनिर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश जारी किए थे ताकि प्रशासनिक मंत्रालय अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के पुनर्गठन/ पुनरुद्धार/ बंद करने के संबंध में समय से कार्रवाई कर सके।

श्री नरेन्द्र मोदी, माननीय प्रधान मंत्री, भारत सीपीएसई कान्कलेव 2018 को संबोधित करते हुए

पिछले 4 वर्षों के दौरान सीपीएसईज़ के कार्यनिष्पादन की कुछ मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :

i) नवीनतम लोक उद्यम सर्वेक्षण के अनुसार सीपीएसईज़ की संख्या वर्ष 2016–17 में 320 से बढ़कर 331 हो गयी हैं।

ii) दिनांक 31.03.2017 तक सभी सीपीएसईज़ में कुल निवेश रु. 12,50,373 करोड़ था जो 31, मार्च 2016 को रु. 11,61,019 करोड़ के निवेश की तुलना में 7.70% अधिक है।

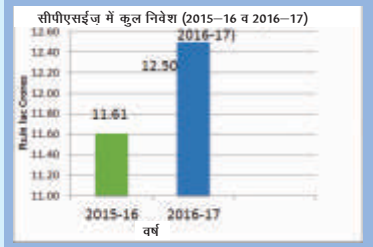

iii) सभी सीपीएसईज़ का निवल मूल्य दिनांक 31.03.2016 को रु. 10,79,753 करोड़ से बढ़कर दिनांक 31.03.2017 को रु. 11,07,981 करोड़ हो गया जो 2.60% की वृद्धि दर्शाता है।

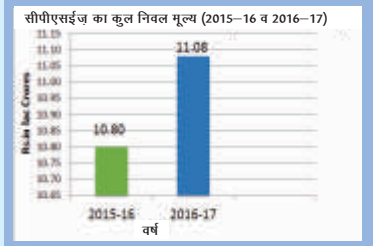

iv) सीपीएसईज़ के समग्र लाभ में 11.70% की वृद्धि हुई है अर्थात वर्ष 2015–16 में रु. 1,14,239 करोड़ से बढ़कर यह वर्ष 2016–17 में रु. 1,27,602 करोड़ हो गया।

v) सभी सीपीएसईज़ का रिजर्व एवं अधिशेष भी वर्ष 2015–16 में रु. 8,98,510 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2016–17 में रु. 9,23,747 करोड़ हो गया जो 2.81% की वृद्धि दर्शाता है।

vi) उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, कॉरपोरेट शुल्क, केंद्रीय सरकारी ऋणों पर ब्याज, लाभांश एवं अन्य शुल्कों द्वारा केंद्रीय राजस्व में सीपीएसईज़ का योगदान वर्ष 2016–17 में रु. 3,85,579 करोड़ है जो वर्ष 2015–16 में रु. 2,75,841 करोड़ की तुलना में 39.78% अधिक है।

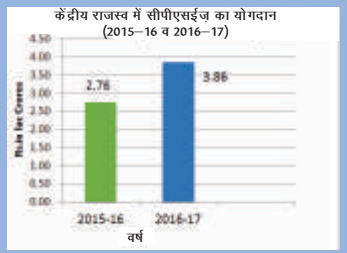

केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के कार्यपालकों एवं अन्य कर्मचारियों के 01.01.2017 से वेतन संशोधन संबंधी दिशानिर्देशों को अगस्त 2017 में जारी किया गया अर्थात वेतन संशोधन देय होने के 8 माह के भीतर इसे जारी किया गया जबकि पिछले वेतन संशोधन 2007 के लिए 22 माह का समय लिया गया था।

केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में वृद्धि के लिए लोक उद्यम विभाग ने मई, 2015 में दिशानिर्देश जारी किए थे, जिसमें उन्हें यह परामर्श दिया गया था कि कौशल विकास और कैरियर में तरक्की के लिए महिला कर्मचारियों को एक समान अवसर उपलब्ध कराए जाएं और इसे केंद्रीय सरकारी लोक उद्यम की मानव संसाधन नीति में एक अनिवार्य हिस्से के रूप में शामिल किया जाए।

लोक उद्यम विभाग ने सितम्बर, 2016 में दिशानिर्देश जारी किए थे जिसमें बंद किए जा रहे केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों की चल और अचल परिसम्पत्तियों के निपटान की प्रक्रिया और पद्धति हेतु समय– सीमा का प्रावधान है। बंद किए जाने वाले केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से इन दिशानिर्देशों में नोशनल 2007 वेतनमानों पर वीआरएस का प्रावधान है चाहे उस केंद्रीय सरकारी लोक उद्यम का विद्यमान वेतनमान कुछ भी हो।

केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की भर्ती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फरवरी, 2016 में लोक उद्यम विभाग द्वारा सभी केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों को दिशानिर्देश जारी किए गए हैं कि वे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार के वर्तमान अनुदेशों के अनुसार मानव संसाधन नीतियां तैयार करें।

लोक उद्यम विभाग, केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के सीएसआर व्यय की निकट से निगरानी कर रहा है और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं/ समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप परिसम्पत्तियों के सृजन के बारे में उन्हें सुग्राही बना रहा है। लोक उद्यम विभाग ने सीपीएसईज़ को अगस्त 2016 में परामर्श जारी किया है कि वे सीएसआर निधियों के 33% का योगदान/ उपयोग स्वच्छ भारत और स्वच्छता संबंधी कार्यों के लिए करें। पिछले तीन वर्षों के दौरान 9815 करोड़ रुपये के कुल सीएसआर व्यय में से लगभग 35% स्वच्छ भारत और अन्य स्वच्छता संबंधी कार्यों पर खर्च किए गए हैं। इसके साथ–साथ केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों द्वारा सीएसआर निधियों के माध्यम से विभिन्न विद्यालयों में 1.39 लाख शौचालयों का निर्माण किया गया है।

गैर– सरकारी निदेशकों (एनओडी) के रिक्त स्थानों को भरने के माध्यम से सीपीएसईज के बोर्डों का व्यवसायीकरण करना। विभिन्न सीपीएसईज के बोर्डों में वर्ष 2014 से गैर– सरकारी निदेशकों के कुल 400 से अधिक पदों को भरा गया है।

सरकार की मेक इन इण्डिया पहल को कार्यान्वित करने के लिए, लोक उद्यम विभाग ने लोक प्रापण में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सेक्टर में स्टार्ट अप के लिए मानदण्डों में छूट हेतु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय और व्यय विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के संबंध में सीपीएसईज के प्रशासनिक मंत्रालयों/ विभागों को सलाह देते हुए नवंबर, 2016 में उपाय किए हैं।

लोक उद्यम विभाग कुछ विशिष्ट सीपीएसईज के केपैक्स की निगरानी कर रहा है और इसकी मासिक रिपोर्ट नियमित आधार पर पीएमओ को भेजी जाती है। इससे सीपीएसईज द्वारा अवसंरचना परियोजनाओं / केपैक्स पर बेहतर व्यय किया गया है। सीपीएसईज ने वर्ष 2015–16 के लिए 85% से कम केपैक्स की तुलना में वर्ष 2017–18 के लिए 110% से अधिक केपैक्स लक्ष्य प्राप्त किए। मॉनीटर किए गए सीपीएसईज के केपैक्स वर्ष 2015–16 में 1.65 लाख करोड रु. से बढकर वर्ष 2017–18 में 2.38 लाख करोड रु. हो गए और इसी अवधि के दौरान रेलवे सहित कुल केपैक्स 3.07 लाख करोड रु से बढकर 4.26 लाख करोड रु हो गए।

लोक उद्यम विभाग ने सरकार को भी इस संबंध में संवेदनशील बनाया है कि ऐसे सीपीएसईज, जिनके पास भारी नकदी और बैंक शेष हैं और अपर्याप्त केपैक्स योजनाएं हैं, को अधिक लाभांश का भुगतान करना चाहिए। इस बात पर भी जोर दिया गया है कि इन सीपीएसईज को शेयरों के पुनः क्रय करने की आवश्यकता है।

समझौता ज्ञापन को पूर्व के प्रक्रियाउन्मुख के बजाए और अधिक परिणामोन्मुख बनाया गया है। समझौता ज्ञापन प्रणाली में लाभकारिता और कार्यक्षमता संबंधी मापदण्डों पर और अधिक जोर दिया गया है। केपैक्स के महत्व को ध्यान में रखते हुए, समझौता ज्ञापन में इसे महत्व दिया गया है। समय और धन की अधिक लागत किए बिना परियोजनाओं को पूरा करने के संबंध में भी सीपीएसईज की निगरानी की जा रही है।

लोक उद्यम विभाग ने जनवरी, 2015 में मंत्रिमण्डल सचिवालय के निष्पादन प्रबंधन प्रभाग के सहयोग से 'एसओईज का निष्पादन मूल्यांकन और प्रबंधन' पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का सफल आयोजन किया। भारत और विदेश के शिक्षाविदों के साथ 12 से अधिक देशों के वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों ने कार्यशाला में भाग लिया और निष्पादन मूल्यांकन और प्रबंधन के क्षेत्रों में श्रेष्ठ पद्धतियों और अनुभवों को साझा किया।

केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के निष्पादन के संबंध में चार लोक उद्यम सर्वेक्षण संसद में प्रस्तुत किए गए।

सीपीएसईज और एसएलपीईज के कर्मचारियों और कार्यपालकों के कौशल विकास के लिए 36 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

लोक उद्यम विभाग ने सरकारी कर्मचारियों से संबंधित एफआर 56(जे) की तर्ज पर सीपीएसईज के कर्मचारियों में सत्यनिष्ठा और कार्यक्षमता की सुनिश्चितता के लिए सीपीएसई की आवधिक समीक्षा हेतु दिसंबर, 2015 में दिशानिर्देश जारी किए।

लोक उद्यम विभाग द्वारा दिसंबर, 2015 में सीपीएसईज में गैर – कार्यकारी पदों की भर्ती के लिए साक्षात्कार को समाप्त करने संबंधी दिशानिर्देश जारी किए।

vii) सीपीएसईज़ का 'निवल मूल्य पर लाभ' वर्ष 2015–16 में 10.58% से बढ़कर वर्ष 2016–17 में 11.52% हो गया है।

viii) केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों द्वारा भुगतान किया गया लाभांश वर्ष 2016–17 के दौरान 13.92% बढ़ गया है। यह वर्ष 2015–16 में रु. 68,583 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2016–17 में 78,133 करोड़ हो गया है।

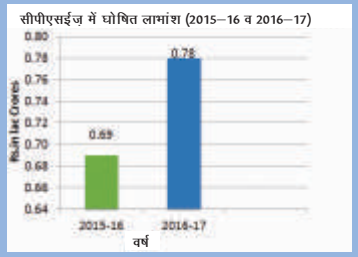

ix) 'सकल ब्लॉक' (चल रहे कार्य को लेकर) के संदर्भ में सीपीएसईज़ में निवेश में समग्र वृद्धि पूर्व वर्ष की तुलना में वर्ष 2015–16 में 6.26% अधिक थी।

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय

आईएसओ: 9001:2008 प्रमाणन

@heindustry | www.dhi.nic.in | www.dpe.gov.in